

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2232
जिसका उत्तर 12 मार्च, 2025 को दिया जाना है
21 फाल्गुन, 1946 (शक)

भारत ट्रेड नेट योजना

2232.कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने केन्द्रीय बजट 2025-26 में उल्लिखित प्रस्तावित भारत ट्रेड नेट (बीटीएन) – एकीकृत व्यापार मंच के अंतर्गत उद्योग 4.0 कार्यक्रम के अवसरों का लाभ उठाने और नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान कर भारत के कुशल कार्यबल की मदद करने हेतु कदम उठाए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सारभूत योजना और समय-सीमा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने उक्त पहल के अंतर्गत कर्नाटक विशेषकर दक्षिण कन्नड़ जिले के कुशल कार्यबल हेतु कोई विशिष्ट योजनाएं तैयार की हैं; और
- (घ) भारत ट्रेड नेट (बीटीएन) योजना के अन्य उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं तथा इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): भारत ट्रेड नेट (बीटीएन) का लक्ष्य सीमा पार व्यापार दस्तावेजों को डिजिटल करना, निर्बाध डेटा एक्सचेंज को समर्थकारी बनाना, व्यापार वित्त को सुविधाजनक बनाना, विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करना और सुरक्षा को बढ़ाना है। वर्तमान में, यह हितधारक परामर्श चरण में है, जो एकीकरण और कार्यान्वयन योजना पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

भारत सरकार द्वाराचिपसेट सहित मुख्य संघटकों के विकास के लिए देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित और संचालित करके और उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए अनुकूलवातावरण बनाकर भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गयी है। इस दिशा में, सरकार ने देश में अर्धचालकों सहित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और उपकरणों में बड़े निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। एमईआईटीवाईने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 (एनपीई 2019) अधिसूचित की, जिसके तहत मंत्रालय द्वारा क्रमशः 34,193 करोड़ रु. तथा 17,000 करोड़ रु. के बजट परिव्यय के साथ बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन योजनाएं, 3,285 रु. करोड़ के बजट परिव्यय के साथ इलेक्ट्रॉनिक संघटकों और अर्धचालकों के विनिर्माणको बढ़ावा देने (एसपीईसीएस) तथा 3,762 करोड़ रु. के बजट परिव्यय के साथ संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर 2.0 (ईएमसी 2.0) नामक प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। इसके अतिरिक्त, देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 76,000 करोड़ रु. के कुल परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है।

इन पहलों के परिणामस्वरूप, पिछले दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का घरेलू उत्पादन वित्त वर्ष 2014-15 में रु.1.90 लाख करोड़ से बढ़कर 17% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर वित्त वर्ष 2023-24 में 9.52 लाख करोड़ रु. (उद्योग के आंकड़े) हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात वित्त वर्ष 2014-15 में 0.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 20% से अधिक की सीएजीआर पर 2.41 लाख करोड़ रु. हो गया है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2023-24 तक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में लगभग 2.5 मिलियन (25 लाख) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन हुआ है (स्रोत: इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए)।

एमईआईटीवाईकीविभिन्न योजनाओं (फरवरी 2025 तक) के तहत कर्नाटक राज्य के संबंध में विशिष्ट विवरण नीचे संक्षेप में दिए गए हैं:

योजना	आवेदनों की संख्या	उत्पादन (करोड़ रु. में)	निवेश (करोड़ रु. में)	रोजगार	निर्यात (करोड़ रु. में)
बड़े पैमाने पर विनिर्माण के लिए पीएलआई	6	94967.11	1915.73	34805	80836.63
आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना (1 और 2.0 संयुक्त)	3	7.89	85.92	59	2.2
इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीईसीएस)	10	633.21	607.08	585	-
संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस)	36	88015.10	9311.7	9419	38114.82
कुल	55	183623.31	11313.35	44868	118953.67

योजना	कुल आवंटित भूमि	भूमि आवंटित करने वाली कम्पनियों की संख्या	उत्पादनाधीन इकाइयाँ	निर्माणाधीन इकाइयाँ	संचयी निवेश मोबलाइज्ड (करोड़ रु. में)	कुल रोजगार
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी)	लागू नहीं	1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	58
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0)	88 एकड़	4	लागू नहीं	1	90	300

सरकार उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न कौशल परियोजनाओं/योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है, जिनमें शामिल हैं:

- (i). एमईआईटीवाई द्वारा ईएसडीएम क्षेत्र में कौशल विकास: पूरे देश में ईएसडीएम क्षेत्र के विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की सुविधा के लिए ईएसडीएम क्षेत्र में कौशल विकास पर दो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिन्हें "इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र में कौशल विकास के लिए चयनित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता के लिए योजना" (योजना-1 और 2) कहा जाता है। योजनाओं के तहत, कुल 4,93,926 अभ्यर्थियों को देश भर में प्रशिक्षित किया गया है और 3,75,295 अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया गया है, जिनमें से 1,38,062 अभ्यर्थियों को ईएसडीएम क्षेत्र में नियुक्त किया गया है। कर्नाटक राज्य में, 20,991 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, 14,789 अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया गया है तथा 7,763 अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया है।
- (ii). एमईआईटीवाई द्वारा सी2एस कार्यक्रम देश भर में फैले 113 शैक्षणिक संगठनों (जिनमें 100 शैक्षणिक संस्थान/आरएंडडी संगठन और 13 स्टार्टअप/एमएसएमई शामिल हैं) में शुरू किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य वीएलएसआई और एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन के क्षेत्र में 85,000 विशेषज्ञ जनशक्ति को प्रशिक्षित करना और चिप/सिस्टम-ऑन-चिप (एसओसी)/सिस्टम लेवल डिज़ाइन की संस्कृति को बढ़ावा देकर ईएसडीएम क्षेत्र में प्रगति करना है। परियोजना के तहत अब तक 43000 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- (iii). एमईआईटीवाई ने 20,000 इंजीनियरिंग छात्रों को 3डी प्रिंटिंग और एडिटिव मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पर प्रशिक्षण देने के लिए सी-डैक, कोलकाता और वेबेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ मिलकर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस परियोजना को पश्चिम बंगाल में 4 संस्थानों और बिहार में 3 संस्थानों के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- (iv). फ्यूचरस्किल्स प्राइम- एमईआईटीवाई ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नेसकॉम) के साथ संयुक्त रूप से "फ्यूचरस्किल्स प्राइम" नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, एडिटिव मैनुफैक्चरिंग / 3डी प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल एंड मोबाइल और साइबर सुरक्षा सहित नई / उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में अभ्यर्थियों का पुनः कौशलन / अप-स्किलिंग करना है।
